



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: ५२-पारे०अनु०-१६/पाट्टाकालि-२०२०-१८/१४ टी०सी०

दिनांक: १८ जनवरी, २०२०

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१ एवं १।),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।

विषय:- विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों/शिकायती पत्रों का निस्तारण उ०प्र० शासन के विभिन्न शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-१३/१/९७-का-१/२०१२, दिनांक १९.०४.२०१२ (छायाप्रति संलग्न) एवं बृदसंलग्नक सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-१३/१/९७-का-१/१९९७, दिनांक ०९.०५.१९९७ द्वारा समूह 'क' तथा तत्कम में निर्गत पत्र संख्या-१३/१/९७-का-१/१९९७, दिनांक ०१.०८.१९९७ द्वारा समूह 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों/शिकायती पत्रों का निस्तारण निम्नवत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करें :-

१. विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।
२. अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जाय।


उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है कि विभाग के विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती पत्रों का निस्तारण उ०प्र० शासन के उपरोक्त आदेशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।


(संथिल पाण्डियन सी०)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : ५२-पारे०अनु०-१६/पाट्टाकालि/२०२०/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
२. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
३. कट फाइल।


(संथिल पाण्डियन सी०)
प्रबन्ध निदेशक

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2)समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (3)समस्त गण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्गिक अनुभाग-1

लखनऊ :: दिनांक 19 अप्रैल, 2012

विषय:-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण।

गहोदय,

कृपया समूह 'क' के अधिकारियों एवं समूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' के सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु कार्गिक विभाग के शासनादेश दिनांक 09 मई, 1997 तथा दिनांक 01 अगस्त, 1997 (सुलग रांदर्ग हेतु प्रतिलिपियाँ संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या-4372(एस0एस0)/2011 कुमदेश कुमार शर्मा बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2012 को आदेश पारित करते हुए निम्नवत् observations किये गये हैं :-

Before parting with the matter, this court would like to observe that the Government Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997, which encompass group 'Kha' 'Ga' and 'Gha' employees of the State Government also, provide for adequate caution to be taken by the authorities concerned while inquiring into the complaints made against the government officers/employees of different categories. However, from the averments made in the counter affidavit filed by the respondents in the instant case, it is clear that the said procedure as provided in the government orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 was not followed. A perusal of the complaint made by Sri Ajay Kumar which has been annexed as annexe No. 4 to the writ petition reveals that the said complaint does not even bear the address of the complainant. The purpose of issuance of the aforesaid two government orders is not only to safeguard the government officers from unnecessary harassment but also to curb the tendency of making frivolous and anonymous complaints against the government servants. The State Government and its authorities by not following the procedure prescribed in the

aforesaid government orders are doing disservice to the society and as such, it would be appropriate to issue a direction to the State Government to ensure that the procedure provided in the Government Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 is adhered to. Accordingly, a direction is issued to the State Government to strictly follow the procedure prescribed under the aforesaid two government orders.

3. अतएव, इस सम्बंध में गुड्रो यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी रोवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निरतारण के प्रत्येक मामले में उपरिसन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 09 मई, 1997 एवं दिनांक 01 अगस्त, 1997 में वर्णित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/1/97(1)-का-1/2012, तददिनांक


प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1. निवन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. मीडिया रालाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी।
7. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. नियुक्ति अनुभाग-6, उ0प्र0 शारान को कार्गिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
9. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
11. सचिवालय के सगस्त अनुगाग।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,


(एच0एच0-गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या 13/1/97-का-1/1997

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्नक दिनांक: 9 मई 1997

विषय : समूह 'क' (श्रेणी - 1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों का निस्तारण।
महोदय,

कार्यक
अनुसार-1

कतिपय स्रोतों से शासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इनमें कुछ माओ सांसदों/विधायकों से प्राप्त शिकायतें होती हैं तथा कुछ अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त होती हैं। कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि शिकायती-पत्रों में अंकित शिकायत कर्ता का नाम फर्जी है तथा शिकायतें निराधार व तथ्यहीन हैं। कतिपय मामलों में किन्हीं विशिष्ट व्यक्ति के पैड का दुरुपयोग करते हुए हस्ताक्षर से शिकायती पत्र दिये जाते हैं।

2-अतः येनामी अथवा फर्जी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए समस्त विधायकसभ द्वारा निर्णय लिया गया है कि समूह 'क' (श्रेणी-1) के सभी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय -

(1) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यो पर आधारित हैं।

(2) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायती की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्ति होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

3-अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि समूह 'क' (श्रेणी-1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शासन के विभिन्न स्तरों पर लघित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगजीत सिंह,
सचिव।

संख्या 13/1/97-का-1/1997, संददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग, उ०प्र० शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०
- (3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
कै० एम० लाल,
विशेष सचिव।

संख्या 13/1/97-का-1/1997

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 01 अगस्त, 1997

विषय : समूह "ख", "ग" तथा "घ" के सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों का निस्तारण।
महोदय,

कार्मिक
अनुभाग-1

कतिपय स्रोतों से समूह "क" (श्रेणी-1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु समसंख्यक शासनादेश दिनांक 09 मई, 1997 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। शरान द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समूह "ख", "ग" तथा "घ" श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु भी समान प्रक्रिया अपनायी जाय। उक्त प्रक्रिया निम्नवत् है :-

(1) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्वन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्वन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उसी के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्वन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

(2) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्वन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

2-अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन के विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगजीत सिंह,
सचिव।

संख्या 13/1/97-का-1/1997, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग, उ०प्र० शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
के० एम० लाल,
विशेष सचिव।